



Neutral Citation No-2026:AHC:6130

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 2940 वर्ष 2025

अभिषेक यादव याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव और 4 अन्य के माध्यम से प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवेश पांडे, धनी राज पांडे, राजेश कुमार,

संतोष कुमार तिवारी, स्वप्नेश सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अनिल कुमार बिंद, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना है जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2 को गांव-छेदखुरी खादर, तहसील-कलां, परगना-जलालाबाद, जिला-शाहजहांपुर की चकबंदी कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया गया है, जो 21.04.2025 से शुरू की गई है और लखनऊ में चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित 21.07.2025 के आवेदन पर उचित कार्रवाई भी की गई है।

II. ऐसी अन्य और आगे उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उपयुक्त समझे। III.

याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत का पंचाट देना।



3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि गांव का चकबंदी अभिलेखों गायब है; इसलिए, कानून की नजर में आगे चकबंदी की कार्यवाही संभव नहीं है। कई अभ्यावेदनों के बावजूद, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

4. स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान चकबंदी निदेशक, लखनऊ द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है; इसलिए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जा सकता है कि वह अपनी शिकायत के संबंध में चकबंदी निदेशक के समक्ष एक नया अभ्यावेदन पेश करे, जैसा कि प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लेख किया गया है।

5. उपर्युक्त के रूप में, प्रस्तुत रिट याचिका को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता को उस दिन के आदेश की प्रमाणित प्रति और प्रस्तुत रिट की स्व-सत्यापित प्रति के साथ अपनी शिकायत के संबंध में चकबंदी निदेशक, लखनऊ के समक्ष एक नया अभ्यावेदन पेश करने की स्वतंत्रता है तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिका। समेकन निदेशक, बदले में, एक जांच करेगा और कानून के अनुसार अभ्यावेदन का निर्णय करेगा, अधिमानतः उक्त अभ्यावेदन प्राप्त करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)